

Naphtha-Based Fertilizer Industry

*1425. **Shri Yogendra Sharma:** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government have explored the possibility of developing the fertilizer industry based on indigenous Naphtha; and

(b) if so, the results thereof?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) Yes, Sir.

(b) Many of the existing factories and almost all the new factories proposed to set up in the Fourth Plan period are based on indigenous naphtha as the raw material.

काश्तकारों को काश्तकारी के अधिकार

*1426. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर राज्यों में काश्तकारों को काश्तकारी के अधिकार देने तथा उनको संरक्षण देने के सम्बन्ध में कानून नहीं बनाये गये हैं और यदि ये कानून बने हैं तो इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या कृषि उत्पादन के मार्ग में यह एक बाधा है; और

(ग) क्या सब काश्तकारों के काश्तकारी के अधिकारों को सुरक्षित रखने, बड़े जमींदारों की फालतू भूमि को भूमिहीन काश्तकारों को देने तथा भूमिहीन ग्रामवासियों को परती भूमि देने के लिये चौथी योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) प्रत्येक राज्य में, काश्तकारी सुधार के बारे में जो कानून बनाये गये हैं, उनकी सूचना योजना आयोग के प्रकाशन "भूमि सुधारों

का कार्यान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद् की भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति की समीक्षा" में दी गई है। यह प्रकाशन हाल ही में प्रचारित किया गया है।

(ख) काश्तकारी सुधार की दिशा में जो कदम उठाये जाते हैं वे कृषि उत्पादन में सुविधा प्रदान करते हैं।

(ग) दशाओं में विभिन्नता है, अतः चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा में जो भूमि सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव हैं वे व्यापक मार्ग-निर्धारण के रूप में हैं। इनका, प्रत्येक राज्य द्वारा स्थानीय दशाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनाया जाना तथा अनुसरण किया जाना है।

Finance Minister's Meeting with Chairman, D.A. Commission

*1427. **Shri K. Lakkappa:**
Shri Hukam Chand Kachwal:
Shri S. S. Kothari:
Shri P. N. Solanki:
Shri Raghuvir Singh
Shastri:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he met Shri Gajendragadkar, Chairman of the Dearness Allowance Commission, recently and discussed the implications of the Commission's recommendations; and

(b) if so, the decision taken by Government on the recommendations of the Commission?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) It is true that Shri Gajendragadkar met me recently. He discussed general matters and not his Report.

(b) Government have not yet taken any decisions on the recommendations of the Commission on Dearness Allowance.